Date
22/04/2020

Subject - New Efforts in Elementary Edu. (D.El.Ed. IInd Sem)
Topic - Kothari Commission

7. स्कूली शिक्षा का विस्तार :- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए निजी क्षेत्रों के आधिपत्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र खोले जायें, जिनमें महिला अध्यापिका को वरीयता दी जाए एवं 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके।
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो व इस स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को कम किया जाए एवं माध्यमिक स्तर पर भी निम्न मा० कक्षाओं में स्वचयन विधि तथा उच्च मा० स्तर पर बाह्य परीक्षा विधि से प्रवेश दिया जाए।

8. स्कूल पाठ्यक्रम :- पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि वि०बो०, शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं व राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शोधकार्य करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को संशोधित करते हुए आयोग ने कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक दो भाषाएँ तथा कक्षा 8 से 10 तक तीन भाषाएँ अनिवार्य होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाजसेवा को स्थान देकर हाथों का नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का मार्ग भी प्रशस्त करना चाहिए।

9. स्कूल शिक्षा पद्धति :- आयोग की दृष्टि से शिक्षा पद्धति, निर्देशन व मूल्यांकन का शिक्षा के नवनिर्माण में अत्यधिक महत्तव है। आयोग ने इस सम्बन्ध में उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों व अध्यापन सामग्री की व्यवस्था एवं निर्देशन एवं विचार-विमर्श को शिक्षा के अंगों में शामिल किया।

Scanned with CamScanner

10. स्कूल निरीक्षण :- आयोग ने शैक्षिक सुधार के लिए सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। निरीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग का पुर्नगठन, शिक्षा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाये, तथा प्रत्येक राज्य मे स्कूल शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाये।

11. उच्च शिक्षा के उद्देश्य :- आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध मे कहा कि विश्वविद्यालयो का कार्य नवीन ज्ञान की खोज करना, व व्यवसायो मे निपुण नागरिको को तैयार करना है। आयोग ने वृहद विश्वविद्यालयो की स्थापना का सुझाव दिया जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विवि॰ के समकक्ष हो। अध्यापन व मूल्यांकन मे सुधार, प्रादेशिक भाषा, उच्च शिक्षा का माध्यम व छात्र अनुशासन को प्राथमिकता दी जाए।

12. उच्च शिक्षा मे प्रवेश व कार्यक्रम :- आयोग ने चयनित प्रवेश नीति का सुझाव दिया। उपयुक्त प्रवेश विधी को विकसित करने के लिए U.G.C. द्वारा केन्द्रीय परीक्षण की स्थापना का प्रस्ताव किया आयोग ने अंशकालीन शिक्षा, नारी शिक्षा का प्रसार, पाठ्यक्रमो का पुर्नगठन, शैक्षिक अनुसंधानो की आवश्यकता पर बल दिया।

Scanned with CamScanner

13. विश्वविद्यालयों की व्यवस्था ⇒ आयोग ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने, आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय स्वायत्ता बनाये रखने व उच्च शिक्षा के उचित विकास के लिए नीति निर्धारण करने संबंधी सिफारिश की।

14. कृषि शिक्षा ⇒ राज्य मे कम से कम एक कृषि विद्यालय खोला जाये, कृषि पोलिटेक्निकों की स्थापना की वरीयता, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाये, कृषि अनुसंधान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपा जाये।

15. व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा ⇒ आयोग ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमो को रोजगार-उन्मुख बनाने तकनीकी पाठ्यक्रमो मे सुधार करने, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमो मे प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्तव देने का सुझाव दिया।

16. विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान ⇒ आयोग ने विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाने, तथा विज्ञान के क्षेत्र मे सफल नेतृत्व के लिए विज्ञान अकादमी के पुर्नगठन की सिफारिश की।

17. प्रौढ़ शिक्षा ⇒ आयोग ने निरक्षरता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, पत्राचार शिक्षा के आयोजन का सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा का सगठंन व प्रशासन करने का सुझाव दिया।

18. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन ⇒ आयोग ने राज्य व स्थानीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन मे सुधार करने का सुझाव दिया।

Scanned with CamScanner